



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 19, 2018/फाल्गुन 28, 1939

No. 150]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 19, 2018/PHALGUNA 28, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2018

सं. 9/2018-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 241(अ).—जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यूरोपीय संघ, ईरान, इंडोनेशिया और जापान (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देश से संदर्भित किया गया है), में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “मेलामाइन” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2933 61 00 के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 48/2012-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 08 अक्टूबर, 2012 के तहत लगाए गए प्रतिपादन शुल्क को जारी रखने के मामले में अधिसूचना संख्या 7/14/2017-डीजीएडी, दिनांक 22 सितम्बर, 2017 जिसे दिनांक 22 सितम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त टैरिफ अधिनियम, 1975 से संदर्भित किया गया है) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपादन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुपालन में सनसैट रिव्यू शुरू की थी;

और जहां कि केन्द्र सरकार ने इन विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं पर लगाए गए प्रतिपादन शुल्क की अवधि को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 47/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 06 अक्टूबर, 2017 जिसे सा.का.नि. 1222 (अ) दिनांक 06 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत 07 अक्टूबर, 2018 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, बढ़ा दी थी;

और जहां कि उक्त विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या एफ सं. 7/14/2017-डीजीएडी, दिनांक 19 फरवरी, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1, में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि ;

- (i) प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने के बाद की स्थिति में घरेलू उद्योग की आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति टिकाऊ एवं मजबूत रही है । विषयगत देशों जैसे कि यूरोपीय संघ, ईरान और जापान से क्षति की अवधि में कोई क्षति नहीं हुई थी । इंडोनेशिया से होने वाले आयात के दौरान भी इस क्षति अवधि में कोई भी क्षति नहीं हुई थी । यहां तक की क्षति अवधि के बाद भी कोई क्षति नहीं हुई थी । इसके अलावा क्षति अवधि के बाद भी विषयगत देशों से होने वाले आयात के कारण कोई क्षति नहीं हुई थी ;
- (ii) इस क्षति अवधि के दौरान कतर से जीएसएफसी के द्वारा किया गया आयात काफी अधिक था । क्षति अवधि के बाद भी होने वाला आयात विषयगत देश से होने वाले आयात मूल्य से कम मूल्य पर था या इसके समतुल्य था । अतः यदि कीमतों में कोई हास आया भी था तो उसके लिए विषयगत देशों से होने वाले निर्यात को कारण नहीं माना जा सकता ;
- (iii) प्रतिपाटन शुल्क से जो संरक्षण की बात है वह विषयगत देशों से होने वाले फालतू आयात के कारण होने वाली सारवान क्षति को रोकने के लिए है और इसका प्रयोग जीएसएफसी के द्वारा निर्धारित प्रतिफल, जो कि अभी होना है, के अंतर्गत उत्पाद की अतिरिक्त क्षमता के संरक्षण के लिए नहीं किया जा सकता है ;

और यूरोपीय संघ, ईरान, इंडोनेशिया और जापान में मूलतः उत्पादित और वहां से निर्यातित "मेलामाइन" के आयात से संबंधित सनसेट रिव्यू को समाप्त करने की सिफारिश की है और इन्होंने यूरोपीय संघ, ईरान, इंडोनेशिया और जापान में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "मेलामाइन" के आयात पर लगाए गए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क को सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 14(ख) के तहत जारी रखने की सिफारिश नहीं की है ।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 48/2012-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 08 अक्तूबर, 2012 जिसे सा.का.नि. 754 (अ) दिनांक 08 अक्तूबर, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा न की गई बातों को छोड़कर, करती है ।

[फा. सं. 354/319/2011-टीआरयू (पार्ट. 1)]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2018

No. 9/2018-Customs (ADD)

G.S.R. 241(E).—Whereas, the designated authority *vide* notification No.7/14/2017 DGAD, dated the 22nd September, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 22nd September, 2017, had initiated the sunset review in term of sub-section (5) of section 9 A of the Customs Tariff

Act, 1975 (51 of 1975), (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of 'Melamine' (hereinafter referred to as the subject goods) falling under the tariff item 2933 61 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in, or exported from originating in or exported from European Union, Iran, Indonesia and Japan (hereinafter referred to as the subject countries), imposed *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 48/2012- Customs (ADD), dated the 8th October, 2012;

And whereas, the Central Government had extended the period of imposition of anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject countries up to and inclusive of the 7th October, 2018 *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 47/2017-Customs (ADD), dated the 6th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1222 (E), dated the 6th October, 2017;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, the Designated Authority in its final findings, published *vide* notification No. F. No.7/14/2017-DGAD, dated the 19th February, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 19th February, 2018 has come to the conclusion that:

- (i) the economic financial parameters of domestic industry post levy of Anti-Dumping Duty were stable and healthy. There was no injury due to imports from subject countries i.e. EU, Iran and Japan during POI. Imports from Indonesia were Nil during injury period and POI and even post POI. Further there was no injury due to imports from subject countries in post POI;
- (ii) the imports made by GSFC from Qatar were significant during injury period, POI and post POI which were either at a price lower than import price from subject countries or comparable. Therefore, price depression if any could not be attributed to exports from the subject countries;
- (iii) protection of Anti-Dumping was for existing capacity of GSFC to address material injury on account of dumped imports from subject countries and cannot be extended for protecting additional capacity of product under consideration being set up by GSFC which is yet to come up;

and has recommended termination of Sunset Review investigation concerning imports of 'Melamine' originating in or exported from European Union, Iran, Indonesia and Japan and has not recommended continuation of existing Anti-Dumping Duty on imports of the 'Melamine' originating in or exported from European Union, Iran, Indonesia and Japan in accordance with rule 14 (b) of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) read with rules 18, 20 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 48/2012- Customs (ADD), dated the 8th October, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 754(E), dated the 8th October, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 354/319/2011-TRU (Pt. I)]
RUCHI BISHT, Under Secy.